



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8542

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 3821/2011

श्रीमती ज्योति एवं अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

नेहा खत्री एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता :राजीव सिसौदिया, सन्तोष कुमार सिंह, शशांक कुमार  
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :अरुण प्रकाश, हरबंध प्रसाद पाण्डेय

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 38

### माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1. वर्तमान अपील दावेदारों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिकर में वृद्धि के लिए, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण /अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, मुजफ्फरनगर द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 74 वर्ष 2010 (श्रीमती ज्योति और अन्य बनाम नेहा खत्री और अन्य) में पारित आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय दिनांक 30.7.2011 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा 23.12.2009 को हुई मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण 30.12.2009 को सचिन कुमार की असामयिक मृत्यु के लिए, दावेदारों को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 14,74,445/- रुपये का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया है, जिसका 80% दोषपूर्ण कार संख्या यू.ए. 07 जी 1313 के बीमाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने का आदेश दिया गया है।

2. चूंकि दोषपूर्ण कार के मालिक, चालक और बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रति-अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए प्रत्यर्थियों द्वारा दुर्घटना के तथ्य और दोषपूर्ण चालक की उपेक्षा पर विवाद नहीं किया गया है।

3. दावेदार-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि सचिन कुमार (मृतक) अपनी मोटरसाइकिल संख्या यू.पी.-11-एस-2228 सावधानी से सड़क के अपनी तरफ चला रहा था, जिसे दोषपूर्ण कार संख्या यू.ए.-07-जी-1313 ने टक्कर मार दी, जिसे तेजी से और

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जो चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.-2 सतीश कुमार द्वारा साबित किया गया था। फिर भी, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की 20% योगदायी उपेक्षा थी, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के विरुद्ध है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषपूर्ण कार ने डिवाइडर पार किया और सड़क की गलत दिशा में आकर दुर्घटना कारित किया।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि किया कि मृतक की 20% उपेक्षा थी। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक का सकल वेतन 13,049/- रुपये प्रति माह था, लेकिन न्यायाधिकरण ने 11,659/- रुपये प्रति माह के वेतन पर प्रतिकर का निर्धारण किया, जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मृतक को भुगतान किए जा रहे सभी भत्तों पर प्रतिकर के निर्धारण के लिए विचार किया जाना था।

5. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस आधार पर कि मृतक की पत्नी, ज्योति को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई थी, न्यायाधिकरण ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं के मद में कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि **विमल कंवर और अन्य बनाम किशोर दान और अन्य (2013) 7 एस.सी.सी. 476** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, प्रतिकर का निर्धारण करते समय मृतक की पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति के तथ्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए** को ध्यान में रखते हुए, दावेदार मृतक की आय के 50% की दर से मृतक की भविष्य की संभावनाओं के मद में प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार थे।

6. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायाधिकरण ने गैर-आर्थिक संबंधी मदों के अंतर्गत अपर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया और 7% प्रति वर्ष के बजाय 6% प्रति वर्ष की दर से कम ब्याज भी अधिनिर्णीत किया गया।

7. इन तर्कों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि दावेदारों द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाए और उन्हें देय प्रतिकर में वृद्धि की जाए।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दुर्घटना के समय मृतक अपनी मोटरसाइकिल तेजी से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था, जिसने दुर्घटना में

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



योगदान दिया, जैसा कि दोषपूर्ण कार की चालक नेहा खत्री के साक्ष्य से साबित होता है, जिसका न्यायाधिकरण के समक्ष डी.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षण किया गया था। अतः, न्यायाधिकरण ने मृतक की ओर से 20% योगदायी उपेक्षा का सही निर्धारण किया। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई थी और उसे 7,100/- रुपये का वेतन और 4,690/- रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी, इसलिए न्यायाधिकरण ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं के मद में सही रूप से कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक को 760/- रुपये मकान किराया भत्ता, 50/- रुपये वाहन भत्ता, 550/- रुपये विशेष आहार भत्ता और 30/- रुपये प्रति माह धुलाई भत्ता मिल रहा था, जो उसके लाभ के लिए व्यक्तिगत भत्ते थे, जिन पर प्रतिकर के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाना है। न्यायाधिकरण ने प्रतिकर का निर्धारण करते समय इन भत्तों को सही रूप से अपवर्जित किया। इन तर्कों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि अपील में कोई गुण-दोष नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

9. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित निर्णय और अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने **जिजू कुरुविला और अन्य बनाम कुंजुजम्मा मोहन और अन्य (2013) 9 एस.सी.सी. 166** के वाद में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"20.5. दुर्घटना के बाद वाहनों की मात्र स्थिति, जैसा कि घटनास्थल के पंचनामे में दिखाया गया है, किसी एक या दूसरे की ओर से तेजी से और उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग के रूप में पर्याप्त प्रमाण नहीं दे सकती है। जब विपरीत दिशाओं से आ रहे दो वाहन टकराते हैं, तो वाहनों की स्थिति और उसकी दिशा, आदि वाहनों की गति, टक्कर की तीव्रता, टक्कर का कारण, वह स्थान जहां एक वाहन ने दूसरे को टक्कर मारी, आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। दुर्घटना के दृश्य से, कोई व्यक्ति उस तरीके का सुझाव दे सकता है या अनुमान लगा सकता है जिसमें दुर्घटना हुई थी, लेकिन किसी प्रत्यक्ष या संपुष्टकारी साक्ष्य के अभाव में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्या चालक की ओर से उपेक्षा थी। ऐसे प्रत्यक्ष या संपुष्टकारी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साक्ष्य के अभाव में, न्यायालय किसी भी व्यक्ति की ओर से उपेक्षा के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दे सकता है।

20.6. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श ए-5 मृत्यु के समय मृतक की स्थिति को दर्शाती है। उक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि मृतक पहले ही भोजन कर चुका था क्योंकि उसका पेट आधा भरा हुआ था और उसमें स्प्रिट की तेज गंध वाले तरल पदार्थ में चावल, सब्जियां और मांस के टुकड़े थे। उपरोक्त साक्ष्य, प्रदर्श ए-5 स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि मृतक ने शराब का सेवन किया था, लेकिन उसी के आधार पर, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि मृतक दुर्घटना के समय कार को तेजी और उपेक्षापूर्वक चला रहा था। प्रदर्श बी-2 "घटनास्थल का पंचनामा" और प्रदर्श ए-5 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मात्र संदेह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, विशेष रूप से तब जब पी.डब्ल्यू. 3 (स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी), प्रदर्श ए-1 (एफ.आई.आर.), प्रदर्श ए-4 (आरोप-पत्र) और प्रदर्श बी-1 (प्रथम सूचना बयान) जैसे प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर हों।"

11. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभावती और अन्य बनाम प्रबंध निदेशक, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 455** के वाद में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"10. हम उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की 25% योगदायी उपेक्षा और 75% बस चालक पर लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। हम इस मुद्दे पर न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करने और प्रदर्शित पी3 घटनास्थल के पंचनामे के अवलोकन के बाद सही निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं था, जो यह दर्शाता हो कि दुर्घटना मृतक की ओर से उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई थी, और पी.डब्ल्यू.1 के मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद, दुर्घटना का कारण केवल दोषपूर्ण वाहन की ओर से तेजी से और उपेक्षा होना अभिनिर्धारित किया।

11. इस प्रकार, हमारे सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की 25% योगदायी उपेक्षा लिया जाना त्रुटिपूर्ण है। हम जिजू कुरुविला बनाम कुंजुजम्मा (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिलेख पर किसी भी प्रत्यक्ष या संपुष्टकारी साक्ष्य के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना दोनों वाहनों

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के तेजी से और उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई थी। इस प्रतिपादन का अनुसरण कुमारी किरण बनाम सज्जन सिंह (2015) 1 एस.सी.सी. 539 में किया गया। इसलिए, वर्तमान वाद में, केवल अभिकथन पर, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि दुर्घटना दोनों वाहनों के तेज गति से चलाए जाने के कारण उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई।"

12. न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदारों ने मृतक की पत्नी श्रीमती ज्योति का पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में, चक्षुदर्शी साक्षी सतीश कुमार लाटियान का पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में परीक्षण कराया है। जबकि, दोषपूर्ण कार चालक श्रीमती नेहा खत्री ने स्वयं का डी.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षण कराया है।

13. श्रीमती ज्योति पी.डब्ल्यू.-1 ने बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थी। पी.डब्ल्यू.-2 सतीश कुमार लाटियान ने गवाही दी कि दुर्घटना 23.12.2009 को रात लगभग 09.00 बजे हुई, जब उसका बहनोई सचिन कुमार (मृतक) अपनी मोटरसाइकिल से विकास नगर, देहरादून से थाना कालसी जा रहा था और जब मृतक विकास नगर में पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तब उसकी मोटरसाइकिल को दोषपूर्ण कार संख्या यू.ए.07-जी-1313 ने आमने-सामने से टक्कर मार दी, जिसे तेजी से और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था, जो सड़क की गलत दिशा की ओर आ गई थी, जिसके कारण मृतक को गंभीर चोटें आईं, जिसे हर्बर्टपुर क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे जॉली ग्रांट अस्पताल, देहरादून रेफर कर दिया गया, जहां 30.12.2009 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसने आगे गवाही दी कि कार दुर्घटना के बाद भाग गई और दुर्घटना को उसके और मृतक के चचेरे भाई अमित ने देखा था, जो पेट्रोल पंप पर अपने वाहन में ईंधन भरवा रहे थे। उसने आगे गवाही दी कि दुर्घटना में मृतक के सिर में गंभीर चोटें आई थी।

14. प्रतिपरीक्षा में उसने गवाही दी कि दोषपूर्ण कार ने मृतक की मोटरसाइकिल को आमने-सामने से टक्कर मारी। उसने आगे गवाही दी कि कार को डिवाइडर के गलत तरफ चलाया जा रहा था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि दुर्घटना मृतक के उतावलेपन और उपेक्षा के कारण हुई थी जो उस समय मोटरसाइकिल चला रहा था।

15. दोषपूर्ण कार चालक श्रीमती नेहा खत्री डी.डब्ल्यू.-1 ने गवाही दी कि दुर्घटना के समय, मृतक अपनी मोटरसाइकिल उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था, जिसके कारण उसकी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मोटरसाइकिल फिसल गई और उसका सिर डिवाइडर से टकरा गया, जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आईं, लेकिन न्यायाधिकरण ने उपरोक्त गवाही पर अविश्वास किया है। उसने स्वीकार किया कि मृतक दुर्घटना के समय अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, जो उसकी कार से टकरा गई, जिसे धीरे और सावधानी से चलाया जा रहा था, जिसके कारण कार का बंपर, रेडिएटर, आगे बाईं ओर की हेडलाइट और आगे का विंड स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने आगे स्वीकार किया कि पुलिस ने उसकी कार जब्त कर ली जिसे बाद में न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया।

16. न्यायाधिकरण ने आपराधिक वाद में तैयार की गई नक्शा-नजरी पर भी विचार किया है, जिससे यह खुलासा हुआ कि दोषपूर्ण कार ने डिवाइडर पार किया और सड़क की गलत दिशा की ओर आ गई और फिर उसने मृतक की मोटरसाइकिल को आमने-सामने से टक्कर मार दी और इसके कारण, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि दोषपूर्ण कार चालक ने दुर्घटना में 80% योगदान दिया जबकि मृतक ने केवल 20% योगदान दिया, जो एक विकृत निष्कर्ष है। पी.डब्ल्यू.-2 के साक्ष्य से यह साबित हुआ कि दोषपूर्ण कार ने डिवाइडर पार किया, सड़क की गलत दिशा में आ गई और फिर मृतक की मोटरसाइकिल से आमने-सामने टकरा गई, जिससे यह साबित हुआ कि दुर्घटना दोषपूर्ण कार चालक की एकमात्र उपेक्षा के कारण हुई।

17. तदनुसार, दुर्घटना में मृतक की योगदायी उपेक्षा के संबंध में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दुर्घटना दोषपूर्ण कार चालक श्रीमती नेहा खत्री के एकमात्र उतावलेपन और उपेक्षा के कारण हुई थी।

18. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव और अन्य (2008) 2 एस.सी.सी. 763** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा अनुलाभों के रूप में भुगतान की गई राशि को उसकी मासिक आय की गणना के लिए शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वह परिवार में योगदान के रूप में उसकी मासिक आय में जोड़ा जाता जो उन लाभों से अलग है, जो उसके लाभ के लिए थे और आय की उक्त राशि से, उस पर देय कर की वैधानिक राशि की कटौती की जानी चाहिए। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि शुद्ध आय का अर्थ सामान्यतया सकल आय में से वैधानिक कटौतियां घटाकर होगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19. **श्यामवती शर्मा और अन्य बनाम करम सिंह और अन्य (2010) 12 एस.सी.सी. 378 और मनस्वी जैन बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (2014) 13 एस.सी.सी. 22 (3 न्यायाधीशों द्वारा)** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक की आय का अभिनिश्चय करते समय, जी.पी.एफ., जीवन बीमा प्रीमियम, ऋण की चुकौती आदि के मद में वेतन प्रमाण पत्र में दिखाई गई किसी भी कटौती को आय से अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। मृतक की शुद्ध आय पर पहुंचने के लिए केवल आयकर/अधिभार के मद में कटौती पर विचार किया जाना चाहिए।

20. **कविता देवी और अन्य बनाम सुनील कुमार और एक अन्य 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1639 और मनोरमा सिन्हा और एक अन्य बनाम द डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2241** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक को भुगतान किए गए भत्ते, जो वेतन में शामिल हैं, चाहे वे कर योग्य हों या नहीं, आय की हानि का निर्धारण करते समय शामिल किए जाने चाहिए क्योंकि उनका उपयोग परिवार के भरण-पोषण के लिए किया जाता है, यदि भत्ते नियमित रूप से प्राप्त होते थे और परिवार के लाभ के लिए उपयोग किए जाते थे।

21. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि दावा वाद में प्रतिकर का निर्धारण करते समय मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जा रहे सभी भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए और मृतक की शुद्ध आय पर पहुंचने के लिए केवल आयकर और अधिभार के मद में काटी गई राशि पर विचार किया जाना चाहिए।

22. यह स्पष्ट है कि मृतक का सकल वेतन 13,049/- रुपये प्रति माह था लेकिन न्यायाधिकरण ने 760/- रुपये एच.आर.ए., 50/- रुपये वाहन भत्ता, 550/- रुपये विशेष आहार भत्ता और 30/- रुपये प्रति माह धुलाई भत्ते को अनदेखा कर दिया है, जो प्रति माह 1,390/- रुपये होता है, और न्यायाधिकरण ने उपरोक्त भत्तों में कटौती के बाद, मृतक का वेतन केवल 11,659/- रुपये प्रति माह मानकर प्रतिकर का निर्धारण किया है। यह सुस्थापित है कि वेतनभोगी कर्मचारी को भुगतान किए जा रहे सभी भत्तों पर प्रतिकर के निर्धारण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है और वेतन पर भुगतान किए गए केवल आयकर की कटौती की जानी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवश्यक है। यह आगे स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त भत्ते मृतक को नहीं दिए गए होते तो निश्चित रूप से उसने उन्हें अपने वेतन से खर्च किया होता जिससे परिवार के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आती और उनकी निर्भरता प्रभावित होती, ऐसे में, प्रतिकर का निर्धारण मृतक के सकल वेतन के आधार पर किया जाना है, जो 13,049/- रुपये प्रति माह था, जिस पर उस समय कोई आयकर देय नहीं था, क्योंकि छूट की सीमा 1,60,000/- रुपये प्रति वर्ष थी।

23. **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 का नियम 220-ए** 26.09.2011 से प्रभावी है, यह अधिदेश देता है कि जब दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी, तो दावेदार उसकी आय के 50% की दर से भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रतिकर के हकदार हैं।

24. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 40,000/- रुपये के दांपत्य साहचर्य की हानि और संपदा की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च के मद में प्रत्येक के लिए 15,000/- रुपये अधिनिर्णीत किए हैं, जिसमें प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 10% की दर से वृद्धि की जानी है।

25. सर्वोच्च न्यायालय ने **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहू राम और अन्य, (2018) 18 एस.सी.सी. 130** के वाद में, पति-पत्नी के साहचर्य, पैतृक साहचर्य और संतान संबंधी साहचर्य के मद में प्रत्येक को 40,000/- रुपये अधिनिर्णीत किए हैं।

26. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल **गणपतराव साबले बनाम लक्ष्मण मारुति जाधव (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से (2023) 13 एस.सी.सी. 334** के वाद में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"32. वर्तमान वाद में, एम.ए.सी.टी. ने दांपत्य साहचर्य की हानि के मद में 5000 रुपये की अल्प राशि प्रदान की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सभी पारंपरिक मदों के अंतर्गत समेकित राशि के रूप में 70,000 रुपये की कुल राशि प्रदान किया, जिसमें दांपत्य साहचर्य की हानि, संपदा की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च शामिल थे। प्रणय सेठी [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एस.सी.सी. 680 : (2018) 3 एस.सी.सी. (सिविल) 248 : (2018) 2 एस.सी.सी. (आपराधिक) 205] में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह प्रावधान किया था कि सभी आश्रितों को दांपत्य साहचर्य की हानि के मद में अलग-अलग

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए और वास्तव में प्रत्येक आश्रित को 40,000 रुपये अधिनिर्णीत किए थे। उसी पर विचार करते हुए, चार आश्रितों में से प्रत्येक को दांपत्य साहचर्य की हानि के मद में 40,000 रुपये अधिनिर्णीत किए जाते हैं।"

(बल दिया गया)

27. एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 2581 वर्ष 2011, सुशील कुमार और एक अन्य बनाम मैसर्स संपर्क लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य, निर्णीत दिनांक 26.04.2017 में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि भले ही दुर्घटना 26.09.2011 से पहले हुई हो, दावेदार उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के संशोधित नियम 220-ए के अनुसार भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकर के हकदार हैं, क्योंकि यह एक लाभकारी विधान है।

28. यह आगे स्पष्ट है कि प्रणय सेठी (उपरोक्त) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए के अनुसार, दावेदार मृतक की आय की 50% की दर से मृतक की भविष्य की संभावनाओं के मद में प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार थे, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसके मद में कोई राशि अधिनिर्णीत नहीं किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यह आगे स्पष्ट है कि उपरोक्त नियम के अनुसार, दावेदार 7% प्रति वर्ष की दर से प्रतिकर पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार थे, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे 6% प्रति वर्ष की दर से अधिनिर्णीत किया है, जिसमें वृद्धि की आवश्यकता है। यह आगे स्पष्ट है कि दावेदार प्रणय सेठी (उपरोक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) और राहुल गणपतराव साबले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए गैर-धन संबंधी मदों के अंतर्गत वर्धित प्रतिकर के हकदार हैं।

29. सेबेस्टियानी लकड़ा और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य, (2019) 17 एस.सी.सी. 465, (3 न्यायाधीशों द्वारा) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकर के निर्धारण के लिए काटी जाने वाली राशि पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"12. विधि सुस्थापित है कि बीमा के कारण, या पेंशनरी लाभों या ग्रेच्युटी के कारण या मृतक के किसी परिजन को रोजगार प्रदान करने के कारण प्रतिकर की राशि से कटौतियों की अनुमति

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नहीं दी जा सकती है। मुख्य कारण यह है कि ये सभी राशियाँ मृतक द्वारा दूसरों के साथ किए गए संविदात्मक संबंधों के कारण अर्जित की जाती हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि ये राशियाँ मोटर वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु के कारण मृतक के आश्रितों या विधिक वारिसों को प्रोद्भूत हुईं। दावेदार/आश्रित मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत "उचित प्रतिकर" के हकदार हैं। इसलिए, स्वाभाविक उप-सिद्धांत यह है कि मृतक की संपदा या उसके आश्रितों को किसी संविदा या कार्य के परिणामस्वरूप जो लाभ प्राप्त होता है जो मृतक ने अपने जीवनकाल में किया था, उसे मृतक की मृत्यु का परिणाम या नतीजा नहीं कहा जा सकता है, भले ही ये राशियाँ उसकी मृत्यु के बाद ही आश्रितों के हाथों में जा सकती हैं।

13. जहाँ तक किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई किसी राशि का संबंध है, जो कुछ भी मृतक की संपदा या उसके आश्रितों में जोड़ा जाता है वह मृतक की मृत्यु के कारण नहीं है बल्कि मृतक और बीमा कंपनी जिसके यहां से उसने पॉलिसी ली थी, के बीच किए गए संविदा के कारण है। मृतक ने ऐसे जीवन बीमा पर प्रीमियम का भुगतान किया और यह राशि पॉलिसी की परिपक्वता पर या उसकी मृत्यु पर, चाहे उसकी मृत्यु का तरीका कुछ भी हो, मृतक की संपदा को प्रोद्भूत होती। इन राशियों का भुगतान इसलिए किया जाता है क्योंकि मृतक ने बुद्धिमानी से अपनी बचत का निवेश किया है। बैंक जमा, शेयर, डिबेंचर आदि जैसे अन्य निवेशों के मामले में भी स्थिति समान होगी। अपकृत्यकर्ता मृतक द्वारा किए गए दूरदर्शिता और बुद्धिमान वित्तीय निवेश का लाभ नहीं उठा सकता है।

14. जहाँ तक पेंशन और ग्रेच्युटी की राशियों का संबंध है, इनका भुगतान मृतक द्वारा अपने नियोक्ता को दी गई सेवा के कारण किया जाता है। सेवा विधिशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन और ग्रेच्युटी मृतक की संपत्ति हैं। वे अधिक आस्थगित मजदूरी की प्रकृति में हैं। मृतक कर्मचारी जीवन भर इस उम्मीद में काम करता है कि सेवानिवृत्ति पर उसे पेंशन और ग्रेच्युटी के रूप में पर्याप्त राशि मिलेगी। मृत्यु का कारण कुछ भी हो, ये राशियाँ मृत्यु पर भी देय हैं। इसलिए, समान सिद्धांतों को लागू करते हुए, उक्त राशि की कटौती नहीं की जा सकती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. जैसा कि पैरी बनाम क्लीवर [पैरी बनाम क्लीवर, 1970 ए.सी. 1 : (1969) 2 डब्ल्यू.एल.आर. 821 : 1969 ए.सी.जे. 363 (एच.एल. ] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, बीमा राशि अतीत में भुगतान किए गए प्रीमियम का फल है, पेंशन पहले से दी गई सेवाओं का फल है और गलत करने वाले को निर्धारित क्षतियों से इसे घटाकर इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

16. कटौती का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है, जब अपकृत्यकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के कारण ही दावेदारों को राशि प्रोद्भूत हुई है।"

30. सर्वोच्च न्यायालय ने **हनुमंतराजू बी. विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम एम. अकरम पाशा और एक अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1106** के वाद में, इस बात पर चर्चा करते हुए कि क्या दावेदार को देय पेंशन को उसकी आय की गणना के लिए काटा जा सकता है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"19. यह भी अब सुस्थापित है कि वेतनभोगी व्यक्तियों के संबंध में प्रतिकर की राशि की गणना घायल/मृतक के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जानी है और आय की गणना के लिए पेंशन और ऐसे सेवानिवृत्ति लाभों की कटौती नहीं की जा सकती है, ये कर्मचारी या उसके विधिक वारिसों द्वारा दुर्घटनाओं, घातक चोटों आदि की किसी भी अप्रत्याशित घटना के बावजूद प्राप्त होने योग्य वैधानिक अधिकार हैं और ऐसा पेंशन लाभ मोटर दुर्घटना से सीधे संबंधित नहीं है। अतः, पेंशन लाभ को 'धन संबंधी लाभ' नहीं माना जा सकता है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दायरे में प्रतिकर की गणना के उद्देश्य से काटे जाने योग्य है। विधि के इस प्रतिपादन के लिए, हम विमल कंवर बनाम किशोर दान (2013) 7 एस.सी.सी. 476 के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एस.आर.टी.सी. (1999) 1 एस.सी.सी. 90 के पूर्व निर्णय का संदर्भ देते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

'19. पूर्वोक्त मुद्दा हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एस.आर.टी.सी. [(1999) 1 एस.सी.सी. 90 : 1999 एस.सी.सी. (आपराधिक) 197] में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। उक्त वाद

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भविष्य निधि, पेंशन, बीमा और इसी प्रकार कोई भी नकद, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा, आदि सभी एक 'धन संबंधी लाभ' हैं जो किसी की मृत्यु के कारण वारिसों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी का किसी संविधि के अंतर्गत प्राप्य राशि के साथ कोई सह-संबंध नहीं है जो केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण प्राप्त होती है। ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में नहीं आएगी, जिसे कटौती के लिए दायी 'धन संबंधी लाभ' कहा जा सके। इस न्यायालय की टिप्पणी और निष्कर्ष निम्नलिखित थे : (एस.सी.सी. पृष्ठ 111-12, प्रस्तर 35)

'35. व्यापक रूप से, हम भविष्य निधि की प्राप्ति का परीक्षण कर सकते हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के कार्यकाल के दौरान किए गए अंशदान में से एक आस्थगित भुगतान है। ऐसा कर्मचारी या उसके वारिस आकस्मिक मृत्यु के बावजूद इस राशि को प्राप्त करने के हकदार हैं। यह राशि सुरक्षित है, प्राप्त होना निश्चित है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत राशि अनिश्चित है और केवल घटना अर्थात् दुर्घटना के घटित होने पर ही प्राप्त की जा सकती है, जो शायद बिल्कुल भी न हो। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी एक कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए सेवा में अपने अंशदान के रूप में सेवा शर्तों के अनुसार अर्जित की जाती है जो उसकी मृत्यु के बाद वारिसों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वारिसों को आकस्मिक मृत्यु के अलावा अन्य स्थिति में भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है। दोनों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। इसी प्रकार, जीवन बीमा पॉलिसी या तो बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वारिसों द्वारा बीमाकर्ता के साथ संविदा के कारण प्राप्त की जाती है, जिसके लिए बीमित व्यक्ति प्रीमियम के रूप में अंशदान करता है। यह बीमित व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है यदि वह सभी प्रीमियम का भुगतान करने के बाद परिपक्वता तक जीवित रहता है। मृत्यु के मामले में, बीमाकर्ता भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए संविदा के अनुसार फिर से वारिसों को राशि का भुगतान करने की क्षतिपूर्ति करता है। पुनः, यह राशि दावेदार द्वारा किसी आकस्मिक मृत्यु के कारण नहीं बल्कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु राशि प्राप्त करने के लिए संविदा के अनुसार केवल एक कदम या आकस्मिकता है। इसी प्रकार, कोई भी नकद, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा आदि यद्यपि सभी एक धन संबंधी लाभ हैं जो किसी की मृत्यु के कारण वारिसों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी का

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण संविधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के साथ कोई सह-संबंध नहीं है। ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में कैसे आ सकती है जिसे कटौती के लिए दायी 'धन संबंधी लाभ' कहा जाए। जब हम हानि और लाभ के सिद्धांत की तलाश करते हैं, तो इसे एक समान और समान तल पर होना चाहिए जिसका उनके बीच आपस में संबंध हो और न कि ऐसा जिसका किसी सह-संबंध का कोई आभास न हो। बीमित व्यक्ति (मृतक) अपने स्वयं के धन का अंशदान करता है जिसके लिए उसे वह राशि प्राप्त होती है जिसका दुर्घटना के कारण उसकी उपेक्षा के लिए अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध गणना किए गए प्रतिकर से कोई सह-संबंध नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में प्राप्य राशि इसके प्रति कोई अंशदान किए बिना चोट या मृत्यु के कारण है, तो फिर बीमित व्यक्ति के अंशदान के माध्यम से प्राप्त राशि के फल को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्य राशि से कैसे काटा जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राशि वह बिना किसी अंशदान के प्राप्त करता है। जैसा कि हमने कहा है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत देय प्रतिकर वैधानिक है जबकि जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्य राशि संविदात्मक है।'

इस प्रकार, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पी.एफ., पेंशन या बीमा के कारण प्राप्य किसी भी राशि को प्रतिकर की गणना के लिए आय या उपार्जन की हानि के निर्धारण के उद्देश्य से पीड़ित के वेतन से नहीं काटा जा सकता है। इस सिद्धांत को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शशि शर्मा (2016) 9 एस.सी.सी. 627 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बीरेंद्र (2020) 11 एस.सी.सी. 356 में दोहराया गया था।"

31. सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेखाबेन और अन्य (2017) 13 एस.सी.सी. 547** के वाद में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"22. वर्तमान वादों में, दावेदारों को अनुकंपा रोजगार की पेशकश की गई थी। दावेदारों को मृतक की आय के बराबर किसी भी धनराशि की पेशकश नहीं की गई थी। वास्तव में, उन्हें किसी भी धनराशि की पेशकश नहीं की गई थी। उन्हें रोजगार की पेशकश की गई थी और जो पैसा वे अपने वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं, वह ऐसे रोजगार से अर्जित किया जाएगा। ऐसे वादों में आय की हानि को मुजरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि दावेदार अपनी आजीविका कमा रहे होंगे।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इसलिए, हमारा विचार है कि दावेदारों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति से अर्जित राशि को अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त प्रतिकर की मात्रा से काटा नहीं जा सकता है।

23. हमारे समक्षवादों में, दोषपूर्ण वाहन के मालिक से प्रतिकर का दावा किया जाता है जो उस नियोक्ता से अलग है जिसने मृतक/घायल के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार की पेशकश की है। वह स्रोत जहाँ से दुर्घटना के कारण प्रतिकर का दावा किया जाता है और वह स्रोत जहाँ से अनुकंपा रोजगार की पेशकश की जाती है, पूरी तरह से अलग हैं और इन दोनों स्रोतों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। चूंकि अपकृत्यकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश नहीं की है, हमारा विचार है कि एक राशि जो कोई दावेदार अपने श्रम से या अपनी सेवाओं की पेशकश करके अर्जित करता है, चाहे अनुकंपा नियुक्ति के कारण या अन्यथा, उस प्रतिकर से काटे जाने योग्य नहीं है जिसे दावेदार अधिनियम के अंतर्गत किसी अपकृत्यकर्ता से प्राप्त करने का हकदार है। ऐसी स्थिति में, हमारा विचार है कि अनुकंपा रोजगार के वित्तीय लाभ को उस प्रतिकर राशि से बिल्कुल भी नहीं काटा जा सकता है जो दोषपूर्ण वाहन के मालिक/चालक या बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने योग्य है।"

32. यह आगे स्पष्ट है कि चूंकि मृतक की कांस्टेबल के रूप में मृत्यु के बाद उसकी पत्नी श्रीमती ज्योति को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जिसे 7,100/- रुपये प्रति माह का वेतन और 4,690/- रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन भी मिल रही थी, न्यायाधिकरण ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं के मद में कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यह सुस्थापित है कि विधिक वारिसों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें अधिनिर्णीत पारिवारिक पेंशन की राशि पर दावा मामले में प्रतिकर का निर्धारण करते समय विचार नहीं किया जाना है। इसके दृष्टिगत, दावेदार मृतक की आय के 50% की दर से मृतक की भविष्य की संभावनाओं के मद में प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं।

33. उपरोक्त वैधानिक विधि और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व-निर्णयों के दृष्टिगत, दावेदारों को देय प्रतिकर का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



| क्र.सं. | प्रतिकर मर्दे                                                               | अधिनिर्णीत राशि (रुपये में) | के अनुसार                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | मृतक की मासिक आय                                                            | 13,049/-                    | मृतक का वेतन प्रमाण पत्र              |
| 2.      | मृतक की वार्षिक आय                                                          | 13,049X12=1,56,588/-        | मृतक का वेतन प्रमाण पत्र              |
| 3.      | व्यक्तिगत खर्चों के मद में 1/4 कटौती (4 आश्रित) घटाएं                       | 39,147/-                    | प्रणय सेठी (उपरोक्त)                  |
| 4.      | शुद्ध वार्षिक आय जिस पर दावेदार निर्भर थे                                   | 1,17,441/-                  | प्रणय सेठी (उपरोक्त)                  |
| 5.      | 50% की दर से भविष्य की संभावनाएं जोड़ें क्योंकि मृतक की आयु लगभग 29 वर्ष थी | 58,720/-                    | उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 |
| 6.      | मृतक पर दावेदारों की कुल वार्षिक निर्भरता                                   | 1,76,161/-                  | प्रणय सेठी (उपरोक्त)                  |
| 7.      | दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 29 वर्ष होने के                            | 17                          | प्रणय सेठी (उपरोक्त)                  |

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



|     |                                                                                                     |                         |                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | कारण लागू किया गया गुणक<br>(Multiplier)                                                             |                         |                                                                                                                |
| 8.  | दावेदारों को निर्भरता की कुल हानि                                                                   | 1,76,161X17=29,94,737/- | प्रणय सेठी (उपरोक्त)                                                                                           |
| 9.  | दांपत्य साहचर्य की हानि @ 40,000/- रुपये प्रत्येक, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि (4 दावेदार) | 48,400X4=1,93,600/-     | प्रणय सेठी (उपरोक्त),<br>मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>(उपरोक्त) और राहुल गणपतराव साबले<br>(उपरोक्त) |
| 10. | संपदा की हानि @ 15,000/- रुपये प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि                                 | 18,150/-                | प्रणय सेठी (उपरोक्त)                                                                                           |
| 11. | अंतिम संस्कार व्यय @ 15,000/- रुपये प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि                            | 18,150/-                | प्रणय सेठी (उपरोक्त)                                                                                           |
| 12. | उपचार व्यय                                                                                          | 49,730/-                | न्यायाधिकरण द्वारा<br>अधिनिर्णीत अनुसार                                                                        |

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



|     |             |             |  |
|-----|-------------|-------------|--|
| 13. | कुल प्रतिकर | 32,74,367/- |  |
|-----|-------------|-------------|--|

34. इस प्रकार, दावेदार 32,74,367/- रुपये के कुल प्रतिकर के साथ दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से इसके वास्तविक भुगतान तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति दोषपूर्ण कार संख्या यू.ए.-07-जी-1313 के बीमाकर्ता द्वारा की जानी है।

35. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय दिनांक 30.07.2011 उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

36. यदि बीमा कंपनी द्वारा पूर्व में किसी राशि का भुगतान किया गया है, तो बीमा कंपनी तदनुसार इसे समायोजित करने की हकदार है। बीमा कंपनी को दो माह के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिकर की वर्धित राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। न्यायाधिकरण दावेदारों को उनकी आयु और निर्भरता को ध्यान में रखते हुए अनुपातिक रूप से प्रतिकर की वर्धित राशि अधिनिर्णीत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(सन्दीप जैन, न्यायमूर्ति)

जनवरी 12, 2026

हिमांशु

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"